

## प्रदेश को जल्द मलिंगी साइबर फॉरेंसिक लैब

### चर्चा में क्यों?

19 मई, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार साइबर अपराधों में जाँच के लिये अब उत्तराखंड पुलिस को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब या अन्य प्रदेशों की लैब पर नरिभर नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही प्रदेश को अपनी फॉरेंसिक लैब मलि जाएगी।

### प्रमुख बदि

- जानकारी के अनुसार इसके लिये केंद्र सरकार द्वारा चार करोड़ रुपए का बजट मंजूर कयि गया है। इसमें से सवा करोड़ रुपए बतौर लमिटि जारी भी कर दयि गए हैं।
- वदिति है कलिगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड का देश में पाँचवां स्थान है, जहाँ सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज कयि जाते हैं। बहुत से मामलों में कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य वस्तुओं को फॉरेंसिक जाँच के लिये केंद्रीय फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजी जाती हैं।
- चंडीगढ़ लैब के ऊपर चंडीगढ़ पुलिस के मामलों की जाँच करने की प्राथमकित्ता रहती है। इसके बाद वह पंजाब और हरयिणा पुलिस को तरजीह देते हैं। ऐसे में उत्तराखंड या अन्य प्रदेशों की पुलिस का नंबर बहुत बाद में आता है।
- पुलिस अधिकारियों के मुताबकि कई बार जाँच रिपोर्ट देरी से आने में मुकदमों की जाँच भी प्रभावति होती है। कोर्ट में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी दबाव रहता है। ऐसे में पछिले साल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापति करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया था।